भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3770**
18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

**पश्चिम बंगाल में डेटा संग्रह अभ्यास**

3770. डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करने और सामाजिक-आर्थिक प्रगति का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वेक्षण अथवा आंकड़े एकत्र करने का कार्य शुरू किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) आकांक्षी जिला कार्यक्रम अथवा अन्य केन्द्रीय पहलों के अंतर्गत सांख्यिकीय आंकड़ों की सटीकता और समयबद्धता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। ये सर्वेक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ गांवों, जो दुर्गम है, को छोड़कर पूरे देश को कवर करते हैं । इन सर्वेक्षणों की रिपोर्ट और उनके निष्कर्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम शक्ति और आर्थिक नियोजन, आदि जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों के अनुमान केंद्रीय प्रतिदर्श डेटा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र भी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित सामाजिक-आर्थिक एनएसएस दौर के सर्वेक्षणों में संबंधित राज्य एजेंसियों/डीईएस के माध्यम से भाग लेते हैं।

(ख) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) सामूहिक प्रयासों का एक परिणाम है जिसमें राज्य मुख्य चालक हैं और इसका उद्देश्य देश भर के 112 सबसे अविकसित जिलों में जल्दी और प्रभावी ढंग से परिवर्तन लाना है। केंद्रीय स्तर पर, इस कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग, जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक प्रगति को गति देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभिन्न विकास भागीदारों के साथ मिलकर काम करता है। एडीपी के तहत, जिले, कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग पद्धति के माध्यम से प्राप्त वित्तीय अनुदानों का उपयोग करके महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं शुरू करते हैं। यह रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों - स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा,

कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास एवं बुनियादी ढाँचे के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में की गई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है। जिलों को सामाजिक-आर्थिक विषयों में सुधार लाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों को विकसित करने और दोहराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन "चैंपियंस ऑफ चेंज" नामक सार्वजनिक डोमेन पोर्टल पर उपलब्ध है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों में सांख्यिकीय डेटा की सटीकता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न सांख्यिकीय उत्पादों में सशक्त और सुपरिभाषित तंत्र नियोजित किए जाते हैं, जिनमें उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बदलती जरूरतों, प्रतिक्रिया और कार्यप्रणाली में प्रगति के आधार पर समय-समय पर सुधार किए जाते हैं। डेटा संग्रह के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन-बिल्ट सत्यापन तंत्र के साथ कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्राथमिक डेटा संग्रह किया जा रहा है। डेटा की सटीकता बहु-स्तरीय डेटा जांच और सत्यापन जांच द्वारा सुनिश्चित की जाती है। संकलात्मक प्रश्नों के समाधान करने और डेटा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक सशक्त प्रशिक्षण तंत्र का पालन किया जाता है।

*****